भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1065

दिनांक 05 फरवरी, 2026 को उत्तरार्थ

बदायूं में विद्युत वितरण परियोजनाएं

1065. श्री आदित्य यादवः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में विद्युत वितरण को मजबूत करने के लिए परियोजनाएं शुरू की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या जिले में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) और चीनी मिलों तथा रासायनिक संयंत्रों जैसी बड़ी औद्योगिक इकाइयों को विश्वसनीय विद्युत अवसंरचना के माध्यम से सहायता प्रदान करने के लिए कोई योजना कार्यान्वित की गई है, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा बदायूं जिले में औद्योगिक विकास को सुगम बनाने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा को अपनाने, पारेषण लाइनों में सुधार करने और विद्युत कटौती को कम करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) से (घ): चूंकि विद्युत एक समवर्ती विषय है**,** अतः उपभोक्ताओं को विद्युत की आपूर्ति और वितरण संबंधित राज्य सरकार/विद्युत यूटिलिटी के अधिकार क्षेत्र में आता है। सूक्ष्म**,** लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) और औद्योगिक इकाइयों सहित सभी उपभोक्ताओं को विश्वसनीय और गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति प्रदान करने के लिए अपनी वितरण अवसंरचना में सुधार और वृद्धि करना संबंधित वितरण यूटिलिटी की जिम्मेदारी है।

भारत सरकार (जीओआई) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनकी वितरण अवसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई), एकीकृत विद्युत विकास स्कीम (आईपीडीएस) और प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) जैसी स्कीमों के माध्यम से सहायता प्रदान कर रही है। वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए 1.85 लाख करोड़ रुपये की परियोजनाओं को निष्पादित किया गया। इसके अलावा, भारत सरकार ने वित्तीय रूप से स्थिर और प्रचालनात्मक रूप से कुशल वितरण क्षेत्र के माध्यम से उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता और विश्वसनीयता में सुधार के उद्देश्य से संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) शुरू की है। स्मार्ट मीटरिंग कार्यों सहित वितरण अवसंरचना कार्यों के लिए 2.83 लाख करोड़ रुपये की परियोजनाओं को स्कीम के तहत संस्वीकृति दी गई है और वे कार्यान्वयन के अधीन हैं। इसमें बदायूं जिले के लिए 529 करोड़ रुपये की लागत वाले कार्य शामिल हैं। संस्वीकृत कार्यों में सब-स्टेशनों और वितरण ट्रांसफार्मरों का उन्नयन / संवर्धन, कंडक्टरों का उन्नयन, मिश्रित-लोड फीडर का पृथक्करण, स्मार्ट मीटरिंग कार्य आदि शामिल हैं।

जैसा कि राज्य द्वारा सूचित किया गया है, बदायूं जिले में एक नया 220 केवी सबस्टेशन बनाया गया है और 132 केवी के 4 सबस्टेशनों को उन्नत किया गया है। इसके अलावा, व्यवसाय योजना 2023-24 और 2024-25 के तहत, 4 नए 33/11 केवी सबस्टेशनों की स्थापना, 33 केवी के 11 फीडरों के सुदृढ़ीकरण और 25 विद्युत ट्रांसफार्मरों की क्षमता वृद्धि के कार्य पूरे हो चुके हैं। इसके अलावा, आरडीएसएस के तहत, 4 नए 33 केवी फीडरों के वितरण अवसंरचना संबंधी कार्य एवं 11 केवी के 34 फीडरों व 109 एलटी फीडरों के सुदृढ़ीकरण संबंधी कार्य पूरे हो चुके हैं। इन सभी कार्यों से बदायूं जिले में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) एवं अन्य औद्योगिक इकाइयों सहित उपभोक्ताओं को विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति में मदद मिलेगी।

प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम) स्कीम के तहत, बदायूं जिले में नवीकरणीय ऊर्जा को अपनाने के लिए, 33 / 11 केवी पावर सबस्टेशनों से कृषि फीडरों के सौरीकरण के लिए सौर संयंत्रों (कुल 74.70 मेगावाट) की संस्थापना के लिए विद्युत क्रय करार (पीपीए) निष्पादित किए गए हैं।

****